[अनुवाद]

तथा उनके पूरे आचरण को मैं विशेषाधिकार समिति को भेज दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक शर्मनाक व्यवहार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को आज की कार्यवाही का एक कैसेट भेज दूंगा। कल आप देखेंगे कि यहां क्या हुआ है। यह शर्मनाक व्यवहार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। इसका निर्णय मैं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक शर्मनाक व्यवहार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम मुझे खेद है कि आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मद संख्या 13, माननीय प्रधान मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल आप यह देखेंगे। यदि आपके पास कुछ समय हो तो उस कैसेट को देखना जो मैं आप सबको भेजूंगा। आपने जिस प्रकार का आचरण किया उसे देश ने देखा है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.11 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा — *जारी*

ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई०ए०ई०ए०) में भारत द्वारा किए गए मतदान के बारे में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 17.2.2006 को दिए गए वक्तव्य पर श्री सी०के० चन्द्रप्पन द्वारा 27.2.2006 को उठाई गई चर्चा पर प्रधान मंत्री डा० मनमोहन सिंह का उत्तर

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (डा० मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में हमारे मतदान के संबंध में मेरे स्वतः दिए गए वक्तव्य के पश्चात हुई चर्चा में माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए हैं। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का आदर करता हूं और इस सम्माननीय सदन में इस विषय पर हुई चर्चा में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर हमारा रूख दूसरे देशों की स्थिति के अनुसार नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र श्री गुरूदास दासगुप्त और श्री सुब्रत बोस ने भी यही विचार व्यक्त किए हैं जैसा कि श्री थारबेल स्वाईं ने कहा है। इसमें कोई दो-राय नहीं हो सकती कि सरकार को कोई पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अथवा दूसरे देशों के कहने पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तथा तथ्यों की पूर्वाग्रहरहित पड़ताल करने के बाद ऐसे मुद्दों पर कोई रूख बनाना सरकार का कर्तव्य है। मैं सम्मान पूर्वक यह कह सकता हूं कि इस मामले में सरकार ने यही किया है। हमने तथ्यों पर विचार किया है तथा कोई रूख अपनाने से पहले अपना स्वतन्त्र निर्णय लिया है। गुट निरपेक्ष नीति का मूल तत्व भी यही है, मेरे मित्र श्री रूपचंद पाल ने इसी का पालन करने का हमसे अनुरोध किया है।

महोदय, मैं मामले के आवश्यक तथ्यों का संक्षेप में ब्यौरा देता हूं :

- ईरान को नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को विकसित करने का विधि सम्मत अधिकार है, परन्तु 'सेफगार्डस एग्रीमेंट' के अनुसार इसके कुछ दायित्व और जिम्मेदारियां भी हैं जिसे उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ स्वैच्छिक रूप से पूरा किया।

[डा० मनमोहन सिंह]

- अनेक अनुत्तरित प्रश्नों की पृष्ठभूमि में ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को विगत अनेक गतिविधियों की जांच में सहायता देने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सहमत हुआ।

- इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग ईरान द्वारा नवम्बर, 2004 में यूरेनियम संवर्धन और पुनः प्रसंस्करण संबंधी सभी गतिविधियों को स्वैच्छिक रूप से बंद कर देना था।

- तथापि, विगत अगस्त से ईरान ने यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का उत्पादन तथा यूरेनियम संवर्धन का कार्य फिर से शुरू कर दिया है।

- सेन्ट्रीफ्यूज आयात और यूरेनियम मेटेलिक हेनिस्फेयर बनाने के डिजाइन संबंधी अनुत्तरित प्रश्न अभी भी बरकरार हैं। यूरेनियम का इस प्रकार से प्रापण सीधे रूप से हमारे लिए चिंता का कारण है।

इन परिस्थितियों में हमारा रूख स्वयं ईरान द्वारा दी गई सूचना और उन तथ्यों पर आधारित था जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा तटस्थ जांच से सामने आए।

अध्यक्ष महोदय, आज अनेक माननीय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड आफ गवर्नर्स की आज होने वाली बैठक के बारे में भी एक प्रश्न उठाया है। श्री चन्द्रप्पन और श्री ओवेसी ने इस बारे में जिक्र किया। मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इस मामले को आज किस रूप में लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पिछले महीने स्वीकृत किए गए संकल्प में कुछ निश्चित उपायों का उल्लेख किया गया है, ईरान तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिन पर चर्चा करेंगे। इस मामले पर वियना में चर्चा चल रही है। सरकार का रूख बातचीत और चर्चा के माध्यम से मामलों का निपटान करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने की हमारी सतत नीति पर आधारित होगा। मैं मानीनय सदस्यों को आश्वास्त करता हूं कि हमारी सरकार सभा में इस संदर्भ में व्यक्त की गई भावनाओं को ध्यान में रखेगी।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अन्य विकल्पों पर विचार किए जाने की संभावना के संबंध में भी कुछ प्रश्न किए गए थे। इस संबंध में ईरान और रूस के बीच भी चर्चा हुई है। हम आशा करते हैं कि सभी पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकल आएगा। हम टकराव, बड़े-बड़े वादे अथवा बाध्यकारी उपायों का समर्थन नहीं करते क्योंकि इनसे केवल क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तथा स्थिति बदतर होती है। भारत ने सतत रूप से यही कहा है कि सभी पक्षों को परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए कार्य करना चाहिए और किसी भी कीमत पर टकराव से बचना चाहिए। इसे संभव बनाने के लिए कूटनीति को कार्यान्वित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं समझता हूं कि संसद और हमारे देश में इस बात पर आम सहमति है कि टकराव भारत या हमारे क्षेत्र के हित में नहीं है। जब भी यह मामला उठेगा, हम इस मसले का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए गुट निरपेक्ष देशों सहित सभी समान विचार रखने वाले देशों के साथ कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मे० ज० खंडूडी सहित अनेक माननीय सदस्यों ने ईरान के साथ हमारे संबंधों तथा इस महत्वपूर्ण संबंध पर इन घटनाओं का प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की है। जैसा कि मैंने अपने स्वप्रेरणा वक्तव्य में कहा कि हमारी सरकार ईरान के साथ विभिन्न प्रकार के परस्पर लाभदायक संबंधों को और गहरा और विस्तृत करने के लिए वचनबद्ध है। अभी हाल ही मेरे सहयोगी विदेश राज्य मंत्री श्री ई० अहमद ने तेहरान का दौरान किया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति श्री अहमदीनिजाद तथा ईरान इस्लामी गणराज्य सरकार के कई मंत्रियों के साथ बैठकें की। श्री अहमद ने वहां पारस्परिक हित के सभी मामलों में ईरान के साथ जुड़े रहने की भारत की इच्छा पर बल दिया। महोदय, मैत्रीपूर्ण तथा लाभकारी संबंधों को और भी गहरा बनाने के बारे में दोनों देशों की प्रतिक्रिया एक समान थी। सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेगी तथा ईरान मुद्दे को पर्याप्त गंभीरता के साथ निपटाएगी। इस मुद्दे पर कार्यवाही करते समय हम ईरान के साथ अपने संबंधों, खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम रखने की आवश्यकता तथा हमारी स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था दुरस्त रखने की ओर समुचित ध्यान देंगे।

महोदय, मैं इस बात को दोहराता हूं कि यह सभा इस बात से आश्वस्त रह सकती है कि हम इस सम्माननीय सभा में व्यक्त की गई भावनाओं को भी ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मुद्दे, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : गोधरा इश्यु बहुत सीरियस इश्यु है, बनर्जी समिति की रिपोर्ट को टेबल किया जाए। *(व्यवधान)*।